तापमान

भोपाल	24.0°	28.0°
इंदौर	24.0°	28.0°
जबलपुर	26.0°	32.0°
ग्वालियर	26.0°	29.0°
सागर	23.0°	29.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 251, पृष्ठ 12)
श्रावण, कृष्ण दशमी संवत् 2083
रविवार, 9 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... मप्र को मिलेंगी चार नई सीधी हवाई ...

व्यापार... पांच दिन में सोना 7,064 और चांदी 14,094 महँगी

खेल... विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिपः पूजा ...

देश-विदेश... पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब में ...

खास-खबरें

यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, सात की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, भरमौरः हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह निजी बस हादसे में सात यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। हादसे में 11 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तीसा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी के अनुसार बस सुबह करीब 7 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी। चालुंज मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई और करीब 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद बस में फंसे लोगों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया।

अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाना हम सभी की जिम्मेदारी : सीजेआई

- संवाद, गरिमा और समावेशन से ही सशक्त बनेगी न्याय व्यवस्था : डॉ. यादव
- मध्यप्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू, इंदौर में वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ

नईदुनिया ब्यूरो, इंदौरः भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस 'इन्हेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस' का शुभारंभ किया। सम्मेलन 9 अगस्त तक चलेगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की पहुंच केवल कानून के आधार पर सुनिश्चित नहीं की जा सकती, इसके लिए संवाद जरूरी है। किसी पीड़ित की समस्या और उसके दुख-दर्द को उसकी अपनी भाषा में समझना होगा। न्याय मिलने से पहले पीड़ित को यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाओं और बच्चों को विधिक

सहायता देना चैरिटी नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालेंटियर्स समाज और न्याय व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। समाज के अंतिम छोर तक न्याय पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। वेस्ट जोन में जनजातीय समुदाय, मछुआरों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों तक विधिक सेवाओं का विस्तार जरूरी है।सम्मेलन में नालसा की शिक्षा स्कीम और थीम सॉन्ग को इंडियन साइन लैंग्वेज में लांच किया गया। नालसा की योजनाओं के हिंदी संस्करण और ब्रेल लिपि में गाइड का विमोचन भी हुआ। जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप प्रोग्राम तथा मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स 'विवाद से सहमति की ओर' का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य न्यायमूर्तियों ने 'न्याय के स्वर' पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्याय पाना प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक और मानवीय अधिकार है। न्याय व्यवस्था सर्वव्यापी, सुलभ, शीघ्र, सस्ती, समदर्शी और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 24 घंटे में इनका गठन किया गया। उन्होंने कहा कि ई-केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा संग्रह, ई-जीरो एफआईआर और आधुनिक तकनीक से न्याय व्यवस्था को अधिक सरल बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री बोले - अगले 35 साल का काम विकसित भारत की नींव बनेगा

सिर्फ सवाल नहीं, समाधान भी खोजें: मोदी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कि आने वाले 35 वर्षों में उनका काम विकसित भारत का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी के सामने अलग चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। आज की पीढ़ी को देश की जरूरतों के अनुसार अपनी भूमिका तय करनी होगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे सिर्फ सवाल न पूछें, बल्कि उनके समाधान भी खोजें। उन्होंने आईआईटी के पूर्व छात्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना, जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। मोदी ने छात्रों को लगातार सीखते रहने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि

दुनिया तेजी से बदल रही है। शिक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन और तकनीक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तकनीक की रफ्तार इतनी तेज है कि अगले 20 से 30 वर्षों में दुनिया कैसी होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में बदलाव के साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए छात्रों को खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि कैंपस की जिंदगी और वास्तविक जिंदगी में काफी अंतर होता है। आईआईटी में पाठ्यक्रम और परीक्षा की जानकारी होती है, लेकिन असली जिंदगी में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। वहां व्यक्ति को खुद यह पहचानना पड़ता है कि असली सवाल क्या है।

'मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं'

प्रधानमंत्री ने छात्रों से हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा।' उन्होंने कहा कि हर छात्र के अपने सपने हैं। कोई पहली सैलरी का इंतजार कर रहा होगा, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता होगा तो कोई नई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होगा। दीक्षांत समारोह में तीन हजार से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें 587 पीएचडी छात्र थे। प्रधानमंत्री ने छात्रों को डिग्री और मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किए।

'परम प्रज्ञा' का उदघाटन

मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित 'परम प्रज्ञा' एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन भी किया। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और शोध में मदद मिलेगी। भारत में नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। ये आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, सी-डैक, आईआईएसईआर और अन्य शोध संस्थानों में लगाए गए हैं।

भागवत के बयान बदलाव का संकेतः कांग्रेस सांसद

मुंबई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है और उसकी मूल विचारधारा में बदलाव नहीं आया है। हालांकि, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों को बदलाव का संकेत बताया। मुंबई में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में थरूर ने कहा कि वह करीब 10 वर्षों से भागवत के बयानों पर नजर रख रहे हैं और अब उनमें बदलाव दिखाई दे रहा है। भागवत ने 6 जुलाई को जेन-जी और जेन-अल्फा से बातचीत में युवाओं को पुरानी पीढ़ी से अधिक देशभक्त और ईमानदार बताया था।

ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का समापन

'भोपाल घोषणा पत्र' जारी, सांस्कृतिक संपदा लौटाने पर 14 देशों की सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में चार दिन से चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का शनिवार को समापन हो गया। संस्कृति मंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक में 'भोपाल घोषणा पत्र' जारी किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने, कलाकारों को अधिक अवसर देने और चोरी या गलत तरीके से विदेश पहुंचाई गई सांस्कृतिक संपदाओं की वापसी के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तीन दिन के विचार-विमर्श के बाद भोपाल घोषणा पत्र के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े क्षेत्रों में साझा रोडमैप तैयार किया गया। इसमें डिजिटल माध्यमों के उपयोग, रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सहयोग पर भी जोर दिया गया। घोषणा पत्र में सांस्कृतिक संपदा के उद्गम-अनुसंधान, उसकी वापसी और पुनर्स्थापन को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्रेसिंग टूल्स की संभावनाओं पर भी काम करने की बात कही गई है। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार के बीच दस्तावेजी विरासत, डिजिटलीकरण और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में कॉपीराइट संरक्षित कृतियों के उपयोग में पारदर्शिता और उचित पारिश्रमिक के विषय को भी घोषणा में शामिल किया गया है।

14 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया

भारत ने ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के तहत स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री विकसित करने की पायलट पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आसान बनाना, पेशेवर नेटवर्क मजबूत करना और ब्रिक्स देशों के कलाकारों तथा रचनात्मक क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ाना है। मंत्री स्तरीय बैठक में भारत सहित 14 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें 10 ब्रिक्स सदस्य देश और चार साझेदार देश शामिल रहे। कुल 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की थीम 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' रही। भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में तीन ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के बाद मंत्री स्तरीय विचार-विमर्श हुआ। भोपाल घोषणा पत्र को सांस्कृतिक सहयोग को व्यावहारिक और संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पुनः परीक्षा की मांग

नईदुनिया ब्यूरो, रांचीः झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन करीब एक घंटे चली बैठक भी बेनतीजा रही। इससे पहले शुक्रवार रात को भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उस दौरान भी कोई समाधान नहीं निकल सका। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छह छात्र अनशन पर हैं। शनिवार सुबह एबीवीपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। छात्रों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के घेराव का

ऐलान किया है। इधर, परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता सत्यम सिंह के अनुसार, राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने याचिका दायर की है। याचिका में परीक्षा दोबारा कराने और कथित धांधली की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कराने समेत चार मांगें रखी गई हैं। राज्य सरकार ने छात्रों से सुझाव लेने के लिए ईमेल और फीडबैक नंबर भी जारी किया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार छात्रों के अलग-अलग समूहों और संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। सभी सुझाव मिलने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

शुक्रवार को भी राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्र नेताओं के बीच बैठक हुई थी। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा था कि बैठक सकारात्मक रही और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा था कि सरकार ने छात्रों की मांगों को समझा है और उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री चमरा लिंडा, सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव बैठक में शामिल हुए।

भारत पर 100% टैरिफ का बिल अमेरिकी सीनेट में पास

- सीनेट में 86-11 से पारित हुआ विधेयक, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी : अमेरिकी सीनेट ने भारत समेत पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाला विधेयक 86-11 के बहुमत से पारित कर दिया है। विधेयक में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना और उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना है।

रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव 23 जुलाई को रखा गया था। विधेयक के शुरुआती मसौदे में 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान था, जिसे बाद में घटाकर 100 प्रतिशत किया गया। हालांकि, अभी यह विधेयक कानून नहीं बना है। इसे अब अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ

रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून लागू हो सकेगा। विधेयक में ईरान के साथ व्यापार करने वाली गैर-अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसके तहत 1996 के ईरान प्रतिबंध कानून को 2031 तक बढ़ाया जा सकता है। यह कानून इसी वर्ष समाप्त होने वाला था।

विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका में आने वाले रूसी सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार भी देगा। यह अधिकार पांच वर्षों तक लागू रहने का प्रावधान है। भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल तेल आयात का 52.4 प्रतिशत था। यानी जून में भारत के आयात किए गए हर दो बैरल में एक से अधिक बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। मई की तुलना में जून में रूस से भारत के कच्चे तेल आयात में करीब 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी विधेयक के पारित होने के बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित टैरिफ को लेकर भारत पर भी असर पड़ने की स्थिति बन सकती है।

जापान में 'डॉल्फिन' का कहर

- 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने का आदेश
- 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा डॉल्फिन तूफान, 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, टोयोटा की 9 फैक्ट्रियों में काम रोका गया

टोक्यो, एजेंसीः जापान में डॉल्फिन तूफान के कारण ओकिनावा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तूफान करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते 2.6 लाख लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। 500

से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं। हालात को देखते हुए टोयोटा ने अपनी नौ फैक्ट्रियों में काम रोक दिया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार डॉल्फिन श्रेणी-1 का तूफान है। इसकी लगातार हवा की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की रफ्तार 198 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। तूफान क्यूशू और ओकिनावा के बीच स्थित द्वीपों की ओर बढ़ रहा है।

भारतीय मैप — *चीन की नाम बदलने की कोशिशों के बीच सरकार का कदम...*

अरुणाचल के 27 स्थान आधिकारिक नक्शे में शामिल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया है। यह कदम चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर पूरी की गई है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सही पहचान को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करना और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

चीन की नाम बदलने की कोशिशों को भारत का जवाब, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी

सरकार के अनुसार, इन जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल करने से प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी रिकॉर्ड में एकरूपता आएगी और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा। इसके अलावा आपदा जैसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने और वहां राहत एवं बचाव कार्य पहुंचाने में भी सुविधा होगी। सरकार की ओर से इन 27 जगहों को आधिकारिक मानचित्र में शामिल करने का उद्देश्य इन क्षेत्रों की प्रशासनिक पहचान को स्पष्ट करना है। इससे सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में इन स्थानों का एक समान उल्लेख किया जा सकेगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन आधिकारिक नामों के आधार पर आम लोगों के पासपोर्ट या अन्य निजी दस्तावेजों में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा या

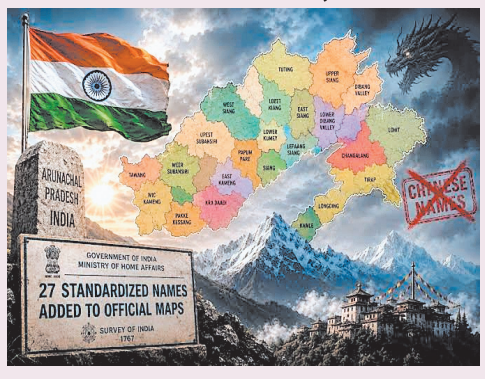

नहीं। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों की आधिकारिक पहचान को तय करना और उन्हें भारत के प्रशासनिक रिकॉर्ड में शामिल करना है। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने की कोशिशें पहले भी सामने आती रही हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और कई बार राज्य की अलग-अलग जगहों के लिए चीनी नामों की सूची जारी कर चुका है। भारत ने चीन की इन कोशिशों को लगातार खारिज किया है। भारत का कहना है कि इस तरह से जगहों के नाम बदलने की कोशिशों का अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। केंद्र सरकार द्वारा 27 जगहों को आधिकारिक नक्शे में शामिल किया जाना भी इन क्षेत्रों की भारतीय प्रशासनिक पहचान को दर्ज करने की दिशा में उठाया गया कदम है।